भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1695

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

'अमृत' के अंतर्गत महाराष्ट्र में मूलभूत अवसंरचना का विकास

+1695. श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चयनित शहरों और कस्बों में मूलभूत अवसंरचना के विकास के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में 'अमृत' के अंतर्गत विकास के लिए चुने गए शहरों और कस्बों के नाम सहित इस योजना का उद्देश्य क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में 'अमृत' के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या 'अमृत' के अंतर्गत योजनाओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 'अमृत' के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विश्व बैंक का आकलन है कि अगले 15 वर्षों में न्यूनतम शहरी अवसंरचना को विकसित करने के लिए लगभग 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके लिए निधियों की व्यवस्था करने की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 शहरों के विलय सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। महाराष्ट्र में, अमृत के तहत 44 शहरों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में अमृत के तहत शामिल शहरों/कस्बों की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

अमृत के तहत परियोजनाओं के लिए आवंटित 35,990 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से में से, वर्ष 2014-15 से अब तक 34,869.15 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अमृत के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता अनुलग्नक-II में दी गई है।

अमृत के तहत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 7,759.32 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) अनुमोदित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 8,011.32 करोड़ रु. की लागत वाली 207 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 7,451.89 करोड़ रु. के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अमृत मिशन और कन्वर्जेन्स के तहत, अब तक 11.73 लाख जल नल कनेक्शन और 4.45 लाख सीवर कनेक्शन [फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के माध्यम से शामिल किए गए आवासों सहित (एफएसएसएम)] प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, अमृत के तहत अब तक 445.7 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन संयंत्र क्षमता (डब्ल्यूटीपी) और 529.5 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता विकसित की गई है।

अमृत के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी अवधि की बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाएं हैं। अमृत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति समय-समय पर अमृत मिशन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों की रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है।

(च) और (छ): विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है *"भारत की शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं का वित्तपोषण: वाणिज्यिक वित्तपोषण की बाधाएं और नीतिगत कार्रवाई की संभावनाएं"* में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत के शहरों को शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और

नगरपालिका सेवाओं में अगले 15 वर्षों में लगभग 840 बिलियन डॉलर के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

जल और स्वच्छता सहित शहरी नियोजन राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। हालांकि, भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं सलाह के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करती है।

शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 500 शहरों में पानी, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन और पार्कों जैसे मुख्य बुनियादी क्षेत्रों पर ध्यान देने के उद्देश्य से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं चलाता है। 77,640 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष, 83,371 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। देश के 500 शहरों से लगभग 4,902 सांविधिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की जा चुकी है। अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर ' और ' जल सुरक्षित ' बनाना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है । जलाशयों का पुनरुद्धार तथा हरित स्थलों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं । अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है ।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निधियां आवंटित की जा चुकी है ।

******

" अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र में मूलभूत अवसंरचना का विकास " के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 1695 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I:

महाराष्ट्र में अमृत योजना के अंतर्गत शामिल शहर

क्र.सं.	शहर का नाम	क्र.सं.	शहर का नाम
1	अचलपुर	23	मालेगांव
2	अहमदनगर	24	मीरा भयंदर
3	आकोला	25	नागपुर
4	अम्बरनाथ	26	नांदेड वाघला
5	अमरावती	27	नंदुरबार
6	औरंगाबाद	28	नासिक
7	बदलापुर	29	नवी मुंबई
8	बार्शी	30	ओसमानाबाद
9	भिवंडी	31	पनवेल
10	भुसावल	32	परभनी
11	बोली	33	पिंपरी चिंचवाड़
12	चंद्रपुर	34	पुणे
13	धुले	35	सांगली-मिरजकुपवाड़
14	गोंदिया	36	सतारा
15	ग्रेटर मुंबई	37	सोलापुर
16	हिंगणघाट	38	ठाणे
17	इचलकरंजी	39	उदगीर
18	जलगांव	40	उल्हासनगर
19	जलना	41	वसई-विरार शहर
20	कल्याणडोंबिवली	42	वर्धा
21	कोल्हापुर	43	यवतमाल
22	लातूर	44	शिरडी

"अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र में मूलभूत अवसंरचना का विकास" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 1695 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II:

पिछले 3 वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए अमृत के तहत राज्यवार जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.32	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	76.37	107.13	-
3	अरुणाचल प्रदेश	56.44	-	-	-
4	असम	179.64	258.84	-	-
5	बिहार	-	-	90.28	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	-	-	-	-
8	दादरा और नगर हवेली	4.16	-	-	-
	दमन और दीव	-	-	-	-
9	दिल्ली	206.2	-	155.53	-
10	गोवा	-	-	41.84	-
11	गुजरात	73.6	-	300	-
12	हरियाणा	147.18	-	9.43	-
13	हिमाचल प्रदेश	66.71	-	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	95.64	-	-	-
15	लद्दाख	-	-	1.8	-
16	झारखंड	109.62	-	-	-
17	कर्नाटक	125.93	-	-	-
18	केरल	119.62	-	207.23	-
19	लक्षद्वीप	0.41	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	100.76	-	-	-
21	महाराष्ट्र	330	-	-	249.94
22	मणिपुर	-	-	-	-
23	मेघालय	22.69	39.42	-	-
24	मिजोरम	-	-	5.65	-
25	नागालैंड	43.52	-	30.69	-
26	ओडिशा	-	-	-	-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
27	पुदुचेरी	9.19	19.66	-	-
28	पंजाब	623.57	-	204.87	-
29	राजस्थान	-	-	53.26	-
30	सिक्किम	18.55	-	2.97	-
31	तमिलनाडु	1454.55	-	828.95	-
32	तेलंगाना	-	-	-	-
33	त्रिपुरा	79.58	-	-	-
34	उत्तर प्रदेश	1418.72	566.88	460.21	-
35	उत्तराखंड	147.02	-	-	-
36	पश्चिम बंगाल	675.26	-	-	-
कुल		6112.88	961.17	2499.83	249.94